

I/172112/2024

Deccan Chronicle -11 May -2024

SOUTHERN INDIA GRAPPLES WITH WATER SCARCITY

New Delhi, May 10: With the southern region most hit at just 15 per cent total live storage capacity in reservoirs, the storage capacity this year is below the average of last 10 years during the corresponding period, the Central Water Commission (CWC) data has revealed.

The CWC's analysis also indicated a week-on-week decrease in storage levels, affecting not only the southern region but also the nation as a whole.

As of last Thursday, the southern region's reservoir capacity stood at 16 per cent, dropping from 17 per cent the previous week.

The bulletin from the CWC said the southern region has been severely impacted, with reservoirs operating at only 15 per cent of their total live storage capacity.

The data from the CWC shows that storage levels this year are lower than both the corresponding period last year and the ten-year average for the same period.

Nationally, out of 150 monitored reservoirs, the total live storage capacity is 178.784 billion cubic metres (BCM), approximately 69.35 per cent of the estimated 257.812 BCM created across the country.

Rajasthan Patrika-11 May -2024

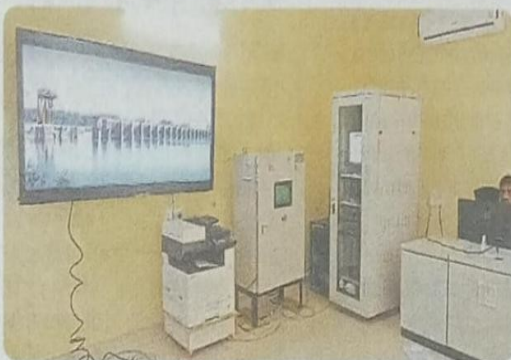
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना में प्रमुख बांधों को किया शामिल प्रदेश की प्रमुख नदियों और बांधों को स्काडा सिस्टम से जोड़ेंगे, केन्द्र की डेटलाइन तय

पत्रिका
रणजीतसिंह सोलंकी
patrika.com

कोटा. टेक्नोलॉजी के दौर में प्रदेश के प्रमुख बांधों और नदियों की डिजिटल कुंडली तैयार की जा रही है। इसमें मानसून में किस नदी और बांध में कितनी रफ्तार से पानी की आवक हो रही है, बांध के कैचमेंट क्षेत्र में कितनी बारिश हो रही है, उसके आधार पर पानी की आवक की स्वचालित यंत्रों से गणना कर डाटा तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर ही बांधों से पानी का डिस्चार्ज किया जाएगा।

पानी के डाटा 12 विभागों को आपस में साझा किया जाएगा। इसमें बाढ़ की स्थिति का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसके आधार पर संबंधित एजेंसियां पहले ही सक्रिय हो जाएंगी और बाढ़ से होने वाली हानि को रोक सकेंगी।

केंद्र सरकार ने प्रदेश की प्रमुख नदियों पर बने बांधों को स्काडा



राणाप्रताप सागर बांध पर लगे हाइड्रैक उपकरण।

56 करोड़ 26 लाख का बजट खर्च

यह परियोजना केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग (विश्व बैंक) की ओर से वित्त पोषित है। परियोजना की कुल

(सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन) से जोड़ने की डेटलाइन तय कर दी है। चंबल नदी के तीनों बांध कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध भी इस

लागत 134.58 करोड़ है। यह परियोजना केंद्र सरकार से अनुदानित है। अब तक परियोजना में 56 करोड़ 26 लाख का बजट खर्च हो चुका है।

परियोजना में शामिल है। इस परियोजना की अवधि मार्च 2024 थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दिया है। अब इस परियोजना का कार्य क्षेत्र पूरे राज्य में है।

यहां काम शुरू होगा

कोटा बैराज, पार्वती बांध घौलपुर, छापी बांध झालावाड़, सोम कमला अम्बा बांध इंगरपुर पर स्काडा सिस्टम स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। नर्मदा नहर परियोजना सांचौर, गंगा नहर तथा भांखड़ा नहर, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ की नहरों पर पारदर्शी जल के लिए स्काडा सिस्टम स्थापित किया जा रहा है। चंबल की नहरों को भी इससे जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान अंतरराज्यीय टेक्निकल कमिटी की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है।

क्या है स्काडा

स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन सिस्टम है। स्काडा प्रणाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है, जो ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी (ओटी) वास्तविक समय डाटा को कैप्चर करके औद्योगिक प्रक्रिया स्वचालन को सक्षम बनाता है। स्काडा उन सेंसरों को जोड़ता है, जो मोटर, पंप और वॉल्व जैसे उपकरणों की निगरानी एक ऑनसाइट या रिमोट सर्वर से करते हैं। वास्तविक समय डाटा प्राप्त हो सकेंगे।

बांधों में पानी की आवक पर निगरानी रखने और बाढ़ नियंत्रण के लिए स्काडा सिस्टम उपयोगी है। स्काडा में अब कोटा बैराज को भी जोड़ा जाएगा। इसके टैंडर की प्रक्रिया चल रही है। - **भारत रत्न गौड़**, अधिशासी अभियंता, जल संसाधन विभाग, कोटा बैराज